भोपाल
सोमवार, 2 फरवरी, 2026
वर्ष 70, अंक 10
पृष्ठ 12
मूल्य रु. 5.00
www.navabharat.net

नव भारत

राष्ट्र हित का प्रहरी
1934 से

बजट 2026-27

पिछले साल से 9 प्रतिशत इस बार अधिक बजट | एमएसएमई को 10 हजार करोड़, अतिरिक्त 4 हजार करोड़ | 800 जिलों में लड़कियों के लिए बनेंगे हॉस्टल | 5 साल में ट्रेड होगा दुगुना

आत्मनिर्भर भारत के लिए ‘सौगातों’ का पिटारा

दिल्ली, नवभारत टीम

नई दिल्ली, 1 फरवरी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में 2026-27 का आम बजट पेश किया. बजट में विशेष तौर पर देश के युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया. इसी के साथ बजट में ‘विकसित भारत 2047’ में सपनों के भारत के तस्वीर की झलक दिखी. वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार नवमीं बार बजट पेश किया, जो कि देश में महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है. ये देश और दुनिया के लिए बड़ी मिसाल साबित हुई. वे 85 मिनट तक बोलीं, टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें इस बार में बजट में पहली बार कही गई. इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी नई रफ्तार : शाह

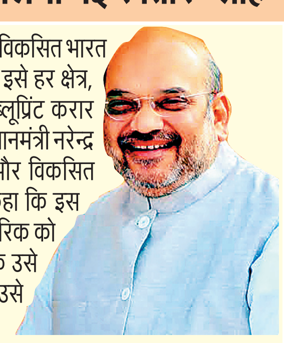

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बताते हुए कहा कि इसे हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का नारा हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा।

भारत रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार : मोदी

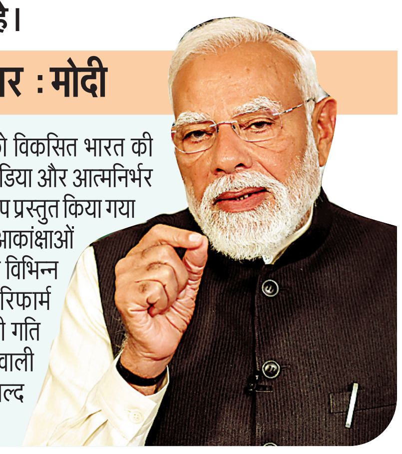

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को विकसित भारत की ऊंची उड़ान का आधार बताया और कहा कि इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट महत्वाकांक्षी भी है और देश की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी भारत जिस रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार है इस बजट से उसे नयी ऊर्जा और नयी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है और वह जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026- 27 का बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है. बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है. यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

वैश्विक चुनौतियों से निपटने से दूर : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बजट 2026-27 बुनियादी संकटों तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने से दूर है और इसमें सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को पूरी तरह से नकार दिया गया है।

दूरदर्शिता तथा दिशाहीन बजट : खरगे

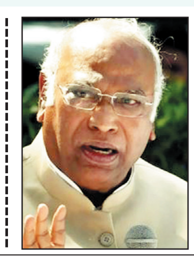

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजट को नीतिगत खालीपन, दूरदर्शिता तथा दिशाहीन करार दिया और कहा है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में चुनौतियों का ठोस समाधान करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं।

आर्थिक दिशा को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश

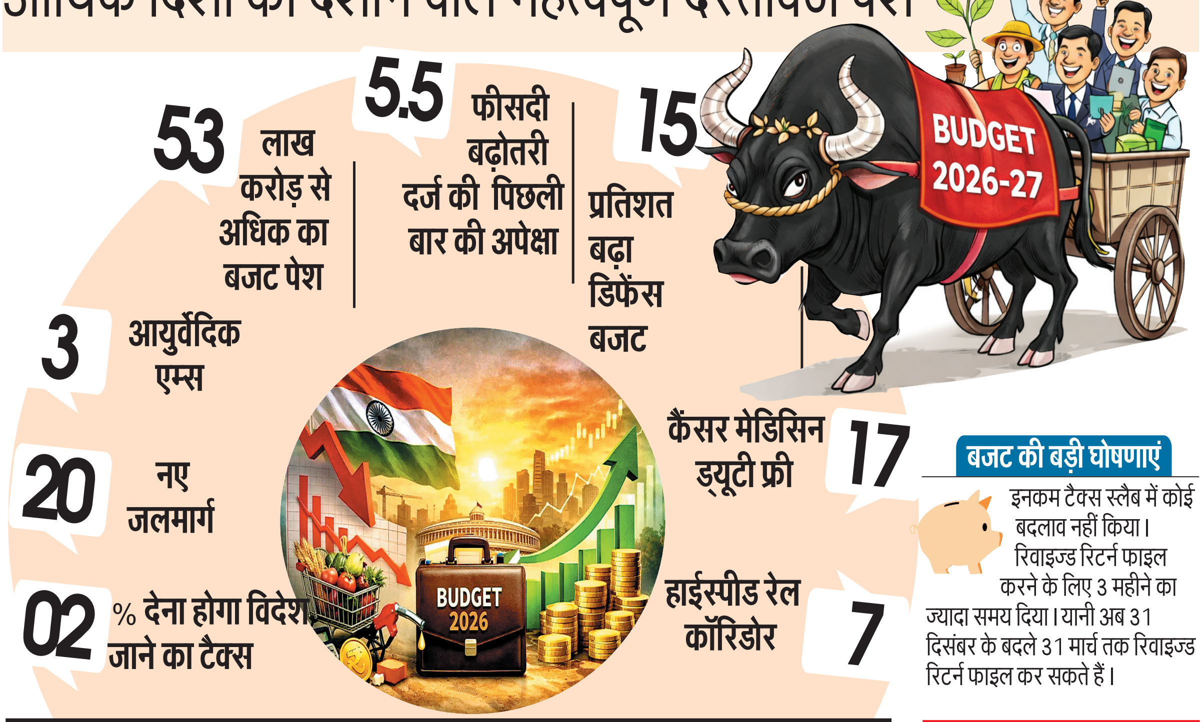

बजट की बड़ी घोषणाएं

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

किसको कितना मिला बजट?

- राजकोष घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत।
- गोल्ड बांड पर नया नियम लागू।
- 20 लाख से कम विदेशी संपत्ति पर टैक्स नहीं।
- इन्कम टैक्स छिपाने पर सजा नहीं लगेगा जुर्माना।
- वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक दिशा को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस बार का कुल बजट 53.47 लाख करोड़ रुपए का है। अगर इसकी तुलना पिछले साल (2025-26) के बजट अनुमानों से की जाए, तो इसमें 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- देश की सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए सबसे अधिक 7,84,678.28 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- गृह मंत्रालय को आंतरिक सुरक्षा और राज्यों की पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2,55,233.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण को गरीबों को मुफ्त अनाज और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2,39,521.37 करोड़ दिए गए हैं।
- रसायन-उर्वरक मंत्रालय को किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1,77,061.47 करोड़ आवंटित हैं।
- कृषि एवं किसान कल्याण को खेती-किसानी और नई योजनाओं के लिए सरकार ने 1,40,528.78 करोड़ का फंड तय किया है।
- शिक्षा मंत्रालय को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए 1,39,289.48 करोड़ का बजट रखा गया है।
- चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और नई स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,06,530.42 करोड़ का आवंटन हुआ है।

क्या होगा सस्ता

- 7 गंभीर रोगों की दवाएं
- कैंसर की 17 दवाएं
- शुगर की दवाई
- विदेश यात्रा
- सीएनजी और बायोगैस
- स्मार्टफोन और टैबलेट होंगे सस्ते

क्या होगा महंगा

- शराब
- स्कैप
- खनिज
- वायदा कारोबार

VISIT A CITROËN SHOWROOM TODAY | 1800 267 1000 +91 7391055934 BHOPAL, ANANTA: 6232920181 INDORE, SATGURU: 7771010416 | I JABALPUR, R&K AUTOCORP: 9238111290/9238111325 | RAIPUR, TOWNIE: 9617774019 | GWALIOR, ANANTA: 7880171606 | SATNA, ARUN BANSAL: 8718807431, 9174407718 | REWA, ARUN BANSAL: 8718807431, 9174407718 IMPHAL, N R TRADERS: 98561 09466 I AGARTALA, PANNA MOTORS : 8794101518 I BHUBANESWAR, AMP WHEELS PVT. LTD.: 70085 32843 I PATNA, KP AUTOMOBILES: 778101 7915 I RANCHI, KP AUTOMOBILES: 77810 17915 I DHANBAD, KP AUTOMOBILES: 7781017915 I JAMSHEDPUR, BHALOTIA: 92638 55077 I ASANSOL, BANERJEE: 8170000423I KOLKATA, CELICA: 90730 64444

*Terms and conditions apply. *Pricing is ex-showroom. The dark glass reflection is for creative representation purposes only. Vehicles & environments shown are AI-generated. Accessories, features and specifications shown may not be part of standard fitment and are subject to change without prior intimation. Actual colour of car and upholstery may differ. #Cara is available only in Basalt X and Aircross X. Always drive safely and obey traffic rules. This pictorial representation of Map of India does not purport to be the political map of India.